

वेल्लेयर पार्टी ऑफ़ इंडिया : क्या और क्यों?

हमारा देश इस समय कई पहलुओं से विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक समाज का हमारा प्रयोग दुनिया के लिए मॉडल बन चुका है। हमारे छात्र, वैज्ञानिक और इंजीनियर अपनी क्षमताओं के कारण विकसित देशों के लिए स्पर्धा का कारण बन चुके हैं। हमारे आर्थिक विकास की पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है। विश्व के धनाढ्य लोगों और विख्यात उद्योगपतियों में भारतीय नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

परन्तु इस विकास की त्रासदी यह है कि इसका लाभ समाज के एक छोटे से वर्ग को मिल रहा है। इस तेज़ रफ़्तार विकास के बावजूद हमारी बहुसंख्य आबादी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी तरस रही है। विश्व की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था हो जाने के बाद भी दुनिया के सबसे अधिक गरीब, भूखे, बेघर, भूमिहीन और मजबूर लोगों की आधा से अधिक संख्या भारतीयों की ही पाई जाती है। हमने स्वतंत्रता की लड़ाई केवल अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने के लिए नहीं लड़ी थी, अर्थात् उसका उद्देश्य कदापि यह नहीं था कि गोरे शासकों को बदल कर काले आकाओं के हाथों में देश के संसाधन दे दिए जाएं। इस संघर्ष के पीछे स्वतंत्र भारत का एक स्वप्न और दूर-दृष्टि (Vision) काम कर रहा था। लक्ष्य केवल यह नहीं था कि शासन करने वाले हाथ बदल दिए जाएं बल्कि वास्तविक लक्ष्य यह था कि शासन का रंग-ढंग बदल जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के छह दशकों बाद भी अभी तक यह सपना पूरा नहीं हो पाया है। आज स्थिति यह है कि भ्रष्टाचार और अनियमितता का चलन भयावह रूप ले चुका है, जिसके आगे पूरी व्यवस्था और सारा सरकारी मशीनरी बेबस नज़र आता है। हर एक को इस बीमारी की भयंकरता की अनुभूति है किन्तु इसका इलाज किसी के बस में नहीं। हर स्तर की राजनीतिक संस्थाएं पूरी तरह से इसकी चपेट में हैं। नौकरशाही इसके कुप्रभाव में पंगु बन चुकी है और अब न्यायपालिका और मीडिया भी इसके शिकंजे में आते जा रहे हैं।

पिछले कुछ सालों से भ्रष्टाचार एक संगठित संस्थागत रूप ले चुका है। पूंजीपतियों, सत्ता पर बैठे लोगों और विरोधी दलों से जुड़े राजनीतिज्ञों, वैश्विक शक्तियों और मीडिया के नापाक गठजोड़ पर आधारित भ्रष्टाचार का नया रूप बहुत ही ऊंचे स्तर के फ़ैसलों पर प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। यह स्थिति लगातार देश को आर्थिक अराजकता की ओर ढकेल रही है।

इस स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारण हमारे शासकों का विकास का त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के तहत पूरा ध्यान केवल धन अर्जित करने पर है। यह सोचे बिना कि धन किन रास्तों से पैदा हो रहा है और इस नए धन का लाभ किस को मिल रहा है। और यह सोचे बिना कि इसके लिए देश की संप्रभुता और आत्मसम्मान के साथ कितने ही गंभीर समझौते करने पड़ें। परिणामस्वरूप कोई नीति बनाते समय आम आदमी से अधिक देश और विश्व के कुछ बड़े पूंजीपतियों का हित सामने रखा जाता है। सरकार का काम बस यह रह गया है कि वह बड़े पूंजीपतियों के कारोबार को फलने-फूलने का अवसर दे, इनके रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करती रहे, इनके कारोबार को चमकाने के लिए हर प्रकार के साधन और आवश्यकताओं को पूरा करती रहे। कृषि और कृषि आधारित उद्योग संकट में हैं और गांवों में अवसर कम से कम होते चले जा रहे हैं। राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का हिस्सा लगातार गिरावट की ओर बढ़ रहा है।

ग्रामीण और शहरी भारत में एक निर्धन आदमी के सर पर उसकी ज़मीन छिन जाने और विस्थापित होने का (Displacement) का ख़तरा निरंतर मंडरा रहा है। ब्याज और सट्टा पर आधारित अर्थव्यवस्था बड़ी तेज़ी से पूंजी को कुछ हाथों में केन्द्रित कर रही है। ग्रामीण प्रदेशों के लोगों के लिए शहरों की ओर पलायन और शहरों में बहुत ही अमानवीय स्थिति में निवास के अतिरिक्त कोई विकल्प बाकी नहीं रह गया है।

ऐसा नहीं है कि इस स्थिति से केवल ग़रीब ही प्रभावित हैं, अपितु इन परिस्थितियों से सबसे अधिक हताश देश का उभरता हुआ मध्य वर्ग है। हमारे प्रोफेशनल्स को ईमानदारीपूर्वक अपने सपनों को साकार करने में कठिनाई महसूस होती है और हमारे मेधावी वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, इंजीनियरों और प्रोफेशनल्स की बड़ी संख्या शिक्षा के बाद विदेश का रुख करने पर स्वयं को मजबूर पाते हैं। क़दम-क़दम पर भ्रष्टाचार और राजनीतिक दखलअंदाज़ी की परंपराएं हमारे व्यापारियों और उद्योगपतियों के उत्साह को कम कर रही हैं। विकास की सारी सांख्यिकी (Statistics) के बावजूद वास्तविकता यह है कि यदि उक्त विकार न होते तो हमारा देश और कहीं अधिक रफ़्तार से विकास करता और विकास के फल से सारा देश लाभान्वित होता।

हमारे देश के कमज़ोर और उपेक्षित वर्ग और अल्पसंख्यक भी न्याय से वंचित हैं, न उन्हें राजनीतिक संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त है और न देश की धन और पैदावार में उनका कोई हिस्सा है। गांव की पुलिस चौकी से लेकर सर्वोच्च प्रशासनिक केन्द्र तक हर स्तर पर 'आम आदमी' पर हिंसा और उसके मानवाधिकार का शोषण सामान्य बात हो गई है। अधिकारियों के अधिकार और उनकी गरिमा को इन्सानी जान से अधिक प्रतिष्ठा मिल चुकी है। ग़रीब ग्रामीण जनता, अल्पसंख्यक और कमज़ोर वर्ग देश के कई क्षेत्रों में भय के साये में जीने को विवश हैं।

देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मुसलमान पिछड़ेपन की दलदल में धंसते-धंसते पिछले छह दशकों में अत्यंत पिछड़ा सामाजिक समूह बन चुका है। शिक्षा और विकास के तमाम पैमानों के हवाले से वे निचले पायदान पर पहुंच चुके हैं। फिर असुरक्षा के जानलेवा एहसास से अभी तक उनको मुक्ति नहीं मिल सकी। आक्रामक साम्प्रदायिकता उन्हें निरंतर आतंकित रखती है। कभी सांप्रदायिक हिंसक घटनाओं के दौरान और कभी आतंकवाद से लड़ने के नाम पर पुलिस और प्रशासन की ओर से उनके विरुद्ध खुले अत्याचार का सिलसिला बराबर जारी है।

फासीवादी और सर्वसत्तावादी रुझान देश के लिए एक गंभीर ख़तरा बनता जा रहा है। संगठित साम्प्रदायिक उन्माद, साम्प्रदायिकता के आधार पर भेदभाव और बायकॉट के सामाजिक परंपराओं का विकास, संप्रदाय विशेष और जाति विशेष के विरुद्ध आतंकवाद के निराधार आरोप के लिए पुलिस ब्यूरोक्रेसी और मीडिया का प्रयोग हक़ और न्याय के लिए संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं की आवाज़ को चुप कराने के लिए उनके विरुद्ध बेबुनियाद मुक़दमे और उन्हें फंसाने की प्रक्रिया में न्यायपालिका का सहयोग, ये सारी घटनाएं जो अब हमारे समाज में सामान्य हो चुके हैं, किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए ख़तरे की घंटी है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और उनका अपने दायरे में स्वतंत्रतापूर्वक काम करना किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए अनिवार्य है। दुर्भाग्यवश, हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यकुशलता अब पतन का शिकार है।

इस परिस्थिति के लिए सबसे अधिक हमारे देश का विशिष्ट राजनीतिक कल्चर उत्तरदायी है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जात-पात और साम्प्रदायिकता की बुनियादों पर परवान चढ़ा यह कल्चर कभी

भी सबके लिए न्याय का पक्षधर और रक्षक नहीं बन सकता। शोषण व अत्याचार, लूट-खसोट और संकीर्ण दुराभाव इस संस्कृति का अनिवार्य परिणाम है। इस संस्कृति का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि समाज के योग्य, बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्तियों का नेतृत्व में कोई भागीदारी नहीं रहती और यह अयोग्य लोगों के हाथों में चला जाता है।

देश की बड़ी राजनीतिक पार्टियां पूरे तौर पर पूंजीपतियों और उनके हितों की गुलाम हैं। भ्रष्ट राजनीतिज्ञों की बड़ी संख्या इनमें हर स्तर पर पहुंच चुकी है। एक बड़े राजनीतिक पार्टी की अल्पसंख्यक दुश्मनी और सर्वसत्तावादी रुझानात काफी मशहूर हैं। जो आन्दोलन पारंपरिक तौर पर पूंजीवाद के खिलाफ और मजदूरों का समर्थक समझे जाते थे वो भी या तो पूंजीपतियों के शिंकजे में फंसते जा रहे हैं या उनकी वर्ग आधारित राजनीति और आउट डेटेड राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराएं नए भारत की उमंगों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अक्षम हैं, जो छोटी पार्टियां उनका विकल्प बन सकती थीं, वो भी वर्ग विशेष, जाति विशेष और क्षेत्र विशेष के हितों के दायरे में इस तरह बंध गयी है कि उनके द्वारा वास्तविक न्याय और समानता का विकास संभव नहीं है। इस प्रकार वास्तविक न्याय और सारे भारतीयों के सामूहिक सपनों को साकार करने के लिए कोई राजनीतिक शक्ति मौजूद नहीं है। परिस्थिति का गंभीर विश्लेषण इस नतीजा पर पहुंचाता है कि भ्रष्टाचार और भौतिकवाद की इस लानत की जड़ वह बेलगाम भौतिकवाद है जिसने पूरे देश को अपने लपेट में ले रखा है। यह लालच और अधिक से अधिक की दौड़ है, जो आदमी को किसी उच्च आदर्श के लिए हित से ऊपर उठकर काम करने के लायक ही नहीं रखती। व्यापार, पूंजीवाद और नौकरशाही के बाद अब राजनीति और जनसेवा भी इसी लालच और भौतिकवाद की गिरफ्त में है।

इस बात से इन्कार मुश्किल है कि उच्च आदर्शों और भौतिकवाद से पाक, हितों से परे सेवाभाव के निर्माण में ईशभय, एक महत्वपूर्ण कारक के तौर पर काम करता है। हमारे देश की राजनीति में धर्म का हमेशा शोषण ही हुआ है और धर्म को लड़ाने, भेदभाव पैदा करने और कमजोरों का शोषण करने के लिए ही प्रयोग किया गया है। भारत जैसे धार्मिक समाज में यदि धार्मिक व आध्यात्मिक मूल्यों को सकारात्मक भूमिका निभाने का अवसर मिले तो इससे यहां सकारात्मक परिवर्तन लाने में बड़ी मदद मिल सकती है। हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष संविधान इसमें बाधक नहीं है। इसलिए कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म का इन्कार नहीं है। बल्कि विभिन्न धर्मों के संबंध में निरपेक्ष रवैया रखना है। आवश्यकता इस बात की है कि धर्मों की आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर हमारी राजनीति को नैतिकता से जोड़ने की कोशिश की जाए।

हमारे संविधान में लोकतंत्र की ऐसी अवधारणा दी थी जिसमें समाज के सभी वर्गों के साथ समानता और उनकी उमंगों की पूर्ति का सामान मौजूद था। परन्तु व्यवहार में हमारा लोकतंत्र, जात-पात और संप्रदायों के आधार पर कुछ इस प्रकार ढल चुका है कि लोकतंत्र पर बहुसंख्यवाद का एहसास होता है। सभी संस्कृतियों को फलने-फूलने और विकास के भरपूर अवसर की संवैधानिक गारंटी के बावजूद व्यावहारिक तौर पर इसके लिए मार्ग प्रशस्त नहीं है।

इस परिस्थिति के ख़ात्मे के लिए केवल हाथों का परिवर्तन काफी नहीं है—कुछ नए राजनीतिज्ञों या राजनीतिक पार्टियों का मैदान में आना काफी नहीं है—लीपापोती या आंशिक और मैकेनिकी परिवर्तन भी काफी नहीं है। आवश्यकता कुछ मौलिक परिवर्तन की है। समाज में हर स्तर पर जागरूकता लाने की आवश्यकता है। एक नयी वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृति दरकार है। नयी राजनीतिक परंपराएं एवं

वातावरण दरकार है। आवश्यकता इस बात की है कि राजनीति और पूंजी के संबंधों को कम किया जाए। राजनीति को एक पेशा और और अथाह धन कमाने का ज़रिया समझने की मानसिकता ख़त्म की जाए। इसे अपराध और अपराधियों से पाक किया जाए। इसे वर्ग संघर्षों का एक हथियार समझने का रुझान भी ख़त्म किया जाए। राजनीति का अपराधीकरण, व्यापारीकरण, साम्प्रदायीकरण और वर्गीकरण हमारी वर्तमान राजनीति की बड़ी बीमारियां हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन बीमारियों के विरुद्ध शक्तिशाली, अवामी और सामाजिक संघर्ष खड़ी की जाए और इसके नतीजे में ऐसे लोग राजनीति में आएँ और उन्हें प्रोत्साहन मिले जिनके सामने सारे देशवासी हों। सबके साथ न्याय की भावना और उच्च आदर्श, मूल्य और सिद्धांत हों।

इन सच्चाइयों को सामने रखते हुए देश के कुछ शुभचिंतक और गंभीर लोगों ने वेल्फेयर पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना का निर्णय लिया है। यह पार्टी ऐसे लोगों पर आधारित होगी जो जनसेवा का बेदाग़ रिकार्ड रखते हों और उच्च आदर्शों के लिए लड़ने और बलिदान की शक्ति रखते हों। पार्टी में हर संप्रदाय, धर्म, जाति और क्षेत्र शामिल रहेंगे और उन्हीं लोगों को दाखिला दिया जाएगा जो पार्टी के सिद्धांतों और दृष्टिकोण के प्रति अपनी वफ़ादारी को कथनी और करनी से साबित कर सकें। यह पार्टी एक वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृति को परवान चढ़ाने की कोशिश करेगी। साथ ही इसकी कोशिश करेगी कि देश के राजनीतिक क्षितिज पर बेआवाज़ों की आवाज़, न्याय की आशा और एक नए भारत की खुशख़बरी बनकर वे स्वयं को उभार सके।

यह राजनीतिक पार्टी राजनीतिक व्यवस्था में सुधार का आन्दोलन होगा और व्यवहार में एक ऐसे कल्याणकारी राज्य को हकीकत का रूप देने की कोशिश करेगी, जिसका आधार मौलिक, नैतिक मूल्य हों और जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के सिद्धांतों पर चलाई जाए। इस उद्देश्य के लिए पार्टी जनअभियान चलाएगी। जनता के राजनीतिक चेतना को जाग्रत करेगी।

आत्मविश्वास और शोषण व अत्याचार से लड़ने का हौसला पैदा करेगी। जनता के बीच कुशल एवं अच्छे नेतृत्व को परवान चढ़ाएगी और इस जागरूकता, चेतना और जनसंघर्ष के द्वारा देश में एक वैकल्पिक राजनीति को उन्नत करेगी।

सिद्धांत और विज़न

सम्पूर्ण न्याय पार्टी का बुनियादी नारा होगा और वह एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहेगी जिसका आधार नैतिक मूल्य, न्याय, समानता, ग़रीबपरवरी, भाईचारा और वास्तविक लोकतंत्र पर हो।

मूल्यों पर आधारित राजनीति : पार्टी एक ऐसी राजनीति को पूरे देश में परवान चढ़ाएगी जो उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित हो। अपराध, भ्रष्टाचार, स्वार्थपरता और संकीर्णता पक्षपात से पूर्ण रूप से पाक हो। इसके लिए आवश्यक है कि जवाबदेही की प्रणाली को चुस्त और सशक्त बनाया जाए। हर बड़े अधिकार के साथ बड़ी जवाबदेही और बड़ी ज़िम्मेदारी से भी जुड़ा हो। बेदाग़ चरित्र, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए मूलभूत शर्त करार पाए।

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा : पार्टी एक कल्याणकारी राज्य के लिए प्रयत्नशील रहेगी। पार्टी के नज़दीक रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज और बुनियादी शिक्षा हर नागरिक के लिए मौलिक मानव अधिकार में शामिल है। नागरिकों की इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एक कल्याणकारी राज्य की ज़िम्मेदारियों में शामिल है।

विकास न्याय व समानता के साथ : पार्टी उद्योग, व्यापार और देश की अर्थव्यवस्था में तेज़ रफ़्तार विकास का विज़न रखती है परन्तु आर्थिक नीतियां इस तरह बनाना चाहती है कि विकास और धनार्जन की प्रक्रिया, न्याय और समानता के मौलिक तर्कों के तहत हो। पूंजी पर इन्सान को प्राथमिकता हासिल हो। धन के केन्द्रीकरण की रोकथाम हो और विकास के फल से सारे भारतीय लाभान्वित हों। आर्थिक विकास के नतीजे में व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ-साथ समाज के पिछड़े और ग़रीब भी ऊपर उठ सकें।

इसके अतिरिक्त पार्टी ऐसा विकास मॉडल चाहेगी जो पर्यावरण की सुरक्षा के साथ हो।

लोकतंत्र, बहुलतावाद और समावेशीकरण : पार्टी सही लोकतांत्रिक आत्मा परवान चढ़ाने की कोशिश करेगी। लोकतंत्र का अर्थ पार्टी के समाने केवल बहुसंख्यक का शासन नहीं बल्कि सभी समूहों के हितों और उमंगों का ख़्याल रखना और सबको साथ लेकर चलने की भावना अर्थात् बहुलतावाद (Pluralism) और समावेशीकरण (Inclusiveness) के मूल्य हैं। इन मूल्यों के विकास के द्वारा एक आदर्श लोकतांत्रिक समाज का निर्माण पार्टी का लक्ष्य होगा। पार्टी का आदर्श लोकतांत्रिक समाज सार्वभौमिक इन्सानी भाईचारे की विचारधारा पर आधारित होगा और जाति, संप्रदाय, नस्ल, क्षेत्र और भाषा की भिन्नताओं से ऊपर उठकर अनेकता में एकता की भावना व संकल्प से परिपूर्ण होगा। सार्वभौमिक भाईचारा की इस भावना का तर्काज़ा होगा कि पसमांदा और पिछड़े हुए भाइयों की तरफ़ सहायता और सहयोग का हाथ बढ़ाया जाए, उन्हें ऊपर उठाया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि उन्हें समाज में प्रतिष्ठा व गरिमा का स्थान मिल सके और विकास की दौरे में वे पीछे न रह पाएं। महिलाओं के लिए विकास के भरपूर अवसर उनके अनुसार उनकी नारीत्व के तर्कों की पूर्ति के साथ उपलब्ध हों।

सांस्कृतिक संघीय चरित्र : पार्टी के वांछित समाज में देश की सभी संस्कृतियों के फलने-फूलने एवं विकास के भरपूर अवसर उपलब्ध रहेंगे। पार्टी का संघीय चरित्र, भौगोलिक और भाषाई पहलू से आगे बढ़कर सांस्कृतिक पहलू को भी सम्मिलित करता है। इसका अर्थ यह है कि भारत के रंगारंग समाज में विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयों को अपने सांस्कृतिक मूल्यों और पहचान की सुरक्षा और उन्नति के भरपूर अवसर, संसाधन और अधिकार प्राप्त रहने चाहिए और व्यक्ति के साथ-साथ सांस्कृतिक समूहों के अधिकारों की भी भरपूर सुरक्षा होनी चाहिए।

